भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 379

मंगलवार, 04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

बिहार में पहले औद्योगिक नोड संबंधी प्रगति

379. श्री राजीव प्रताप रूडीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में औद्योगिक गलियारों के अंतर्गत विकसित किए जा रहे पहले औद्योगिक नोड के संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस नोड के विकास के लिए सरकार द्वारा कितना वित्तीय आवंटन किया गया है और अब तक स्वीकृत और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना के पूरा होने में कोई विलंब हुआ है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बिहार राज्य में इस नोड के विकास से अपेक्षित रोजगार-क्षमता और आर्थिक लाभ का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एकेआईसी) के भाग के रूप में बिहार राज्य के गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) के विकास हेतु भारत सरकार की आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने अगस्त 2024 में अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

आईएमसी गया के विकास के लिए कुल 1,339 करोड़ रुपए की परियोजना लागत अनुमोदित की गई है। इसमें भारत सरकार से इक्विटी के रूप में 462 करोड़ रुपए का अंशदान तथा ऋण के रूप में 345 करोड़ रुपए की राशि को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना से लगभग 1 लाख रोजगार के सृजन और लगभग 16,500 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होने की संभावना है।

इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु, बिहार सरकार, बीआईएडीए और राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) के बीच राज्य सहायता समझौता (एसएसए) तथा बीआईएडीए और एनआईसीडीआईटी के बीच शेयरधारक समझौता (एसएचए) निष्पादित किया गया है। एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) - बिहार इंटीग्रेटिड मैन्यूफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड (बीआईएमसीजीएल) का भी गठन किया गया है। इस परियोजना में कोई विलंब नहीं हुआ है और निर्माण-पूर्व कार्यकलाप शुरू कर दिए गए हैं।

*****